International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

बिहार में पहचान की राजनीति : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

विकाश कुमार विधाता

शोधार्थी
स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

शोध–सार

बिहार की राजनीति लंबे समय से पहचान आधारित विमर्शों के इर्द–गिर्द विकसित होती रही है, जिसमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता प्रमुख कारक रहे हैं। यह अध्ययन बिहार में पहचान की राजनीति के स्वरूप, विकास और उसके सामाजिक–राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दशकों में राजनीति पर उच्च जातियों का प्रभुत्व रहा, किंतु 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सामाजिक न्याय की राजनीति ने नई दिशा प्राप्त की। इस परिवर्तन ने पिछड़ी और दलित जातियों को राजनीतिक रूप से सशक्त किया और सत्ता संरचना में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा। इस आलेख में यह देखा गया है कि पहचान की राजनीति ने एक ओर सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक विभाजन, ध्रुवीकरण और विकासात्मक मुद्दों से ध्यान भटकाने का कारण भी बनी। धार्मिक पहचान, विशेषकर मुस्लिम समुदाय की राजनीति, भी बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय असमानताएं और भाषा आधारित पहचान भी राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करती हैं। बिहार में पहचान की राजनीति एक दोधारी तलवार के समान है, जो सशक्तिकरण और विभाजन दोनों को जन्म देती है। अतः आवश्यक है कि पहचान आधारित राजनीति को समावेशी विकास, सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संतुलित किया जाए। यह शोध नीति–निर्माताओं और विद्वानों के लिए उपयोगी दृष्टिकोण प्रदान करता है।

शब्दकुंजी : सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व, राजनीतिक भागीदारी, समावेशी विकास, सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक मूल्य आदि

परिचय :

बिहार भारतीय राजनीति का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पहचान की राजनीति ने गहरी जड़ें जमा रखी हैं। पहचान की राजनीति का अर्थ उन राजनीतिक प्रक्रियाओं से है, जिनमें व्यक्ति या समूह अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या जातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक दावे प्रस्तुत करते हैं। बिहार में यह प्रक्रिया विशेष रूप से जाति आधारित रही है, जिसने न केवल चुनावी राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि सामाजिक संरचना और शक्ति संतुलन को भी पुनर्परिभाषित किया।

स्वतंत्रता के बाद बिहार में राजनीति मुख्यतः उच्च जातियों के नियंत्रण में थी। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ जैसे समुदायों का प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे पर प्रभुत्व था। किंतु यह स्थिति लंबे समय तक नहीं बनी रही। 1960 और 1970 के दशक में सामाजिक असमानताओं के खिलाफ आवाज उठने लगी। यह प्रक्रिया 1990 के दशक में चरम पर पहुँची, जब मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिला। इससे राजनीति में एक नई सामाजिक शक्ति का उदय हुआ।

लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की राजनीति ने बिहार में एक नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने एम.वाई. (मुस्लिम–यादव) समीकरण के माध्यम से एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया। इससे न केवल पिछड़ी

जातियों का सशक्तिकरण हुआ, बल्कि मुस्लिम समुदाय को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। इस दौर में पहचान की राजनीति ने सामाजिक न्याय को केंद्र में रखा, लेकिन इसके साथ ही प्रशासनिक अक्षमता और विकास की कमी की आलोचना भी हुई।

इसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजनीति ने विकास और सुशासन की ओर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन पहचान की राजनीति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। उन्होंने अति पिछड़ा और महादलित जैसी श्रेणियों को सामने लाकर नई पहचान आधारित राजनीति को जन्म दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि बिहार की राजनीति में पहचान का महत्व आज भी बना हुआ है।

धार्मिक पहचान भी बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुस्लिम समुदाय, जो राज्य की एक बड़ी आबादी है, चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाता है। विभिन्न राजनीतिक दल उनके समर्थन के लिए रणनीतियाँ बनाते हैं। इसके अलावा, हाल के वर्षों में हिंदुत्व की राजनीति का भी प्रभाव बढ़ा है, जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति देखी जा सकती है।

भाषाई और क्षेत्रीय पहचान भी राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करती हैं। मिथिलांचल, मगध, भोजपुर और सीमांचल जैसे क्षेत्रों की अपनी–अपनी सांस्कृतिक पहचान है, जो स्थानीय राजनीति को प्रभावित करती है। सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी अधिक होने के कारण वहाँ की राजनीति अलग दिशा में विकसित होती है।

इस प्रकार, बिहार में पहचान की राजनीति बहुआयामी है, जिसमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता सभी शामिल हैं। यह राजनीति एक ओर सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी ओर यह समाज को विभाजित भी करती है। इस अध्ययन का उद्देश्य इन सभी पहलुओं का विश्लेषण करना है, ताकि बिहार की राजनीति को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

उद्देश्य :

- बिहार में पहचान की राजनीति के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करना।
- जाति, धर्म और क्षेत्रीय पहचान के राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करना।
- पहचान की राजनीति के सामाजिक और लोकतांत्रिक प्रभावों का मूल्यांकन करना।
- समावेशी और संतुलित राजनीतिक विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

साहित्य की समीक्षा :

बिहार में पहचान की राजनीति को समझने के लिए क्रिस्तोफ जाफरेलो (2003)[1] का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने भारत में पिछड़ी जातियों के राजनीतिक उदय को एक "शांत क्रांति" के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार मंडल राजनीति ने बिहार में सत्ता के सामाजिक आधार को पूरी तरह बदल दिया और वंचित समूहों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाया।

आशीस नंदी (1999)[2] पहचान आधारित राजनीति को केवल सत्ता संघर्ष नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रतिरोध के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार बिहार जैसे समाजों में यह राजनीति आधुनिकता के विरुद्ध परंपरागत सामाजिक संरचनाओं के पुनर्स्थापन का माध्यम भी है।

योगेंद्र यादव (1999)[3] ने चुनावी राजनीति में जाति की निर्णायक भूमिका को रेखांकित किया है। उनका तर्क है कि बिहार में मतदान व्यवहार मुख्यतः जातीय पहचान से संचालित होता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विशिष्ट रूप देता है।

घनश्याम शाह (2002)[4] ने दलित राजनीति के उदय और उसके सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण किया है। वे बताते हैं कि पहचान की राजनीति ने दलितों को राजनीतिक चेतना और अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

बद्री नारायण (2011)[5] ने सांस्कृतिक राजनीति के संदर्भ में पिछड़े और दलित वर्गों की पहचान निर्माण प्रक्रिया को समझाया है। उनके अनुसार लोक–संस्कृति और प्रतीकों के माध्यम से राजनीतिक लामबंदी की जाती है।

प्रभात पटनायक (2010)[6] ने आर्थिक असमानता और पहचान की राजनीति के बीच संबंध को स्पष्ट किया है। वे मानते हैं कि आर्थिक विषमता पहचान आधारित राजनीतिक आंदोलनों को जन्म देती है।
जावेद आलम (2004)[7] ने मुस्लिम राजनीति और उसके प्रतिनिधित्व का अध्ययन करते हुए बताया कि बिहार में मुस्लिम पहचान राजनीतिक गठबंधनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
नंदिनी सुंदर (2007)[8] ने क्षेत्रीय और आदिवासी पहचान की राजनीति को विश्लेषित किया है। उनके अनुसार क्षेत्रीय असमानताएँ भी पहचान आधारित राजनीतिक संघर्षों को जन्म देती हैं।
सुभाष सी. कश्यप (2010)[9] ने भारतीय लोकतंत्र में पहचान की राजनीति के प्रभावों को समझाते हुए कहा कि यह लोकतंत्र को एक ओर समावेशी बनाती है, वहीं दूसरी ओर विभाजनकारी प्रवृत्तियों को भी जन्म देती है।
रामाश्रय राय (1999)[10] ने बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों और सत्ता संरचना के बीच गहरे संबंध को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार राज्य की राजनीति को समझने के लिए जाति–आधारित पहचान का विश्लेषण अनिवार्य है।

बिहार में पहचान की राजनीति :

जातीय पहचान ने न केवल चुनावी रणनीतियों को प्रभावित किया है, बल्कि सामाजिक संबंधों और संसाधनों के वितरण को भी निर्धारित किया है। मंडल आयोग के लागू होने के बाद पिछड़ी जातियों का राजनीतिक उदय हुआ, जिससे सत्ता संरचना में व्यापक बदलाव आया। इस परिवर्तन ने लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया, लेकिन साथ ही जातीय ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा दिया। धार्मिक पहचान भी बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुस्लिम समुदाय, जो राज्य की लगभग 16–17 प्रतिशत आबादी है, चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाता है। विभिन्न राजनीतिक दल उनके समर्थन के लिए विशेष रणनीतियाँ बनाते हैं। हाल के वर्षों में हिंदुत्व की राजनीति के प्रभाव से धार्मिक ध्रुवीकरण में वृद्धि देखी गई है। क्षेत्रीय पहचान भी राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करती है। सीमांचल, मिथिलांचल और मगध जैसे क्षेत्रों की अपनी–अपनी समस्याएं और प्राथमिकताएं हैं। इन क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दे और पहचान राजनीति को दिशा देते हैं।
पहचान की राजनीति का एक सकारात्मक पहलू यह है कि इससे वंचित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला है। पिछड़ी और दलित जातियों को सत्ता में भागीदारी का अवसर मिला, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि यह राजनीति अक्सर विकास और शासन के मुद्दों से ध्यान भटका देती है। इसके अलावा, पहचान की राजनीति ने राजनीतिक दलों को भी प्रभावित किया है। दल अपनी रणनीतियाँ जातीय और धार्मिक समीकरणों के आधार पर बनाते हैं। इससे राजनीति में विचारधारा की बजाय पहचान का महत्व बढ़ गया है। इस प्रकार, बिहार में पहचान की राजनीति एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू मौजूद हैं।

निष्कर्ष :

बिहार में पहचान की राजनीति ने राज्य के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया है। इसने वंचित और पिछड़े वर्गों को सशक्त किया है और उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, जो लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंडल राजनीति के बाद उत्पन्न सामाजिक न्याय की लहर ने सत्ता के केंद्रीकरण को तोड़ा और समाज के विभिन्न वर्गों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल किया। हालांकि, पहचान की राजनीति के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए हैं। यह राजनीति अक्सर सामाजिक विभाजन और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है, जिससे समाज में तनाव और असमानता बनी रहती है। इसके अलावा, यह विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटका देती है। वर्तमान समय में आवश्यकता है कि पहचान की राजनीति को समावेशी विकास और सामाजिक समरसता के साथ संतुलित किया जाए। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे केवल पहचान आधारित राजनीति न करें, बल्कि विकास और सुशासन को भी प्राथमिकता दें।

अंततः, बिहार की राजनीति में पहचान एक महत्वपूर्ण तत्व बनी रहेगी, लेकिन इसे सकारात्मक दिशा में ले जाना ही राज्य के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।

संदर्भ–सूची :

1. Jaffrelot, Christophe (2003) : 'India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India'. New York: Columbia University Press, pp. 1-520.
2. Nandy, Ashis. (1999) : 'The Romance of the State and the Fate of Dissent in the Tropics'. New Delhi: Oxford University Press, pp. 1-240.
3. Yadav, Yogendra. (1999) : 'Electoral Politics in the Time of Change: India's Third Electoral System'. 'Economic and Political Weekly', Vol. 34, No. 34-35, pp. 2393-2399.
4. Shah, Ghanshyam. (2002) : 'Dalits and the State'. New Delhi: Concept Publishing Company, pp. 1-300.
5. Narayan, Badri. (2011) : 'The Making of the Dalit Public in North India'. New Delhi: Oxford University Press, pp. 1-280.
6. Patnaik, Prabhat. (2010) : The Political Economy of Inequality. 'Social Scientist', Vol. 38, No. 9-10, pp. 3-16.
7. Alam, Javed. (2004) : 'Who Wants Democracy\' New Delhi: Orient Longman, pp. 1-200.
8. Sundar, Nandini. (2007) : 'Subalterns and Sovereigns: An Anthropological History of Bastar'. New Delhi: Oxford University Press, pp. 1-350.
9. Kashyap, Subhash C. (2010) : 'Our Constitution: An Introduction to India's Constitution and Constitutional Law'. New Delhi: National Book Trust, pp. 1-350.
10. Roy, Ramashray. (1999) : Bihar: The Janata Dal Years. New Delhi: B.R. Publishing Corporation, pp. 1-250.